तियां जमा नहीं करवाई । पुनर्मिलान न होने की वजह से विसंगतियां होने के कई कारण हैं जिनमें से प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति अस्थिर होने के कारण कई बार राज्य सरकार द्वारा ट्रकों को बीच में ही रोक लिया जाता है और भारतीय खाद्य निगम की सहमति/सूचना के बिना उनसे माल उतार लिया जाता है;

(2) कभी-कभी कर्फ्यू/बंद होने की वजह से घाटी में कई-कई दिनों तक ट्रक रुके रह जाते हैं ।

(ख) यद्यपि 116 ट्रकों के ऐसे मामलों को राज्य की पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है जिनके बारे में जांच करने पर यह पाया गया था कि वे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे भारतीय खाद्य निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप सिद्ध होता हो ।

(ग) जिन ट्रकों का पुनर्मिलान नहीं हुआ है वे जम्मू से श्रीनगर घाटी में ले जाए जा रहे थे । जब तक पुनर्मिलान करने का कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक ये ट्रक लापता हो गए नहीं कहे जा सकते हैं ।

(घ) 116 ट्रकों के मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो/स्थानीय पुलिस को सौंप दिए गए हैं और जांच कार्य पूरा हो जाने के बाद ही इन मामलों में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के अंतर्ग्रस्त होने के बारे में जानकारी मिल पाएगी ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छत्तीसगढ़ में चीनी मिल

5079. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ (रायपुर दुर्ग जिलों) में एक चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्तावित चीनी मिल की अनुमानित लागत क्या होगी और इस परियोजना हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) चीनी के उत्पादन का कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) बिबकोनी पारशवनी, तहसील महासमुंद, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में 2500 टी. सी. डी. क्षमता की एक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए उद्योग मंत्रालय के माध्यम से मै. छत्तीसगढ़ चीनी मिल लि. से दिनांक 4-3-94 को एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ग) प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री की अनुमानित लागत जैसा कि आवेदक पार्टी ने सूचित किया है 32 करोड़ रुपये होगी । तथापि, केन्द्र सरकार नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं करती है ।

(घ) और (ङ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं क्योंकि तैयार करने हेतु गठित समिति ने चीनी

के वर्षवार उत्पादन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :—

वर्ष	चीनी का उत्पादन (लाख टन)
1992–93	121.68
1993–94	127.76
1994–95	134.13
1995–96	140.84
1996–97	147.88

Fixing of levy price of sugar

5080. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR : Will the Minister of FOOD be pleased to state what decision Government have taken on the request of the Maharashtra Government to include the expenditure incurred on harvesting and transportation of sugarcane while fixing the levy price of sugar ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : The matter is under examination.

Problem of new sugar factories in Maharashtra

5081. DR. SHRI KANT RAMCHANDRA JICHKAR : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government is aware of the problems faced by the 36 new sugar factories in Maharashtra to which letters of intent have been given ;

(b) what is the progress made by the committee appointed to take review for reducing the project cost of these factories : and

(c) what is Government's reaction to the suggestion by the Government of Maharashtra in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) Yes Sir. The financial institutions had indicated that the applications of sugar factories in the co-operative sector for term loans would be considered only after the respective State Governments arranged for clearance of defaults committed by the existing sugar and textile cooperative units whose loans had been guaranted by the State Governments. In view of the speedy clearance by the Government of Maharashtra of the defaults committed by the sugar cooperatives, the central financial institutions have now started processing of the cases pertaining to Maharashtra.

(b) and (c) A Group was constituted to review the standard list of equipments of a new sugar factory, civil works and lay out design of the plant with a view to exploring the possibilities of reducing the cost of new sugar projects without affecting capacity and efficiency of the sugar mill plants. The report submitted by this Group in 1991 has been accepted by the Government. The report was forwarded to all State Governments, including the Government of Maharashtra, for necessary action.

Most of the records have been demaged brunt in the fire that broke-up in Krishi Bhavan on 16-10-1992. As such, the suggestion made by the Government of Maharashtra in this regard, if any, is not available.